भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2081

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मार्च, 2015 को दिया जाना है

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान

2081. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान शुरू किया है जिससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण करने वाले लाभान्वित होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2012-13 के 42,000 ई वाहनों की तुलना में वर्ष 2013-14 में लगभग 20,000 वाहन ही बेचे हैं;

(घ) क्या सरकार ने ई वाहन और हाइब्रिड वाहन बनाने वाली कंपनियो कों प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश में हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना था। वर्ष 2020 से आगे वर्ष दर वर्ष 6~7 मिलियन हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री प्राप्त करना इसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। सरकार का उद्देश्य इस नवोदित प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने के लिए राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन देना है। सरकार से सहायता के साथ वर्ष 2020 तक संचयी बिक्री 15~16 मिलियन तक पहुँचने की आशा है। इससे 9500 मिलियन लीटर अशोधित तेल अर्थात् ₹62,000 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। सरकार ने केन्द्रीय बजट 2015-16 में ₹75 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ एनईएमएमपी 2020 के अंतर्गत फास्टर अडॉपशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम इंडिया) नामक एक योजना की शुरूआत की है। यह योजना देश में हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी वाले, दोनों प्रकार के वाहनों के शीघ्र अंगीकरण तथा बाजार सृजन को एक बड़ा बल प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का जोर हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को क्रेताओं की प्रथम पसंद बनाने पर रहेगा ताकि ये वाहन परंपरागत वाहनों को प्रतिस्थापित कर सकें जिससे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में तरल ईंधन की खपत में कमी होगी। यह परिकल्पना की गई है कि मांग प्रोत्साहन, आंतरिक प्रौद्योगिकी विकास तथा घरेलू उत्पादन के माध्यम से बाजार का शीघ्र सृजन करने से उद्योग को वर्ष 2020 के आसपास दीर्घकाल में आत्मनिर्भर तथा मितव्ययिता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(ग): उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2012-13 में 42,000 इलेक्ट्रिक वाहन तथा वर्ष 2013-14 में लगभग 20000 हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए थे। वर्ष 2012-13 में बेचे गए अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक कम स्पीड वाले स्कूटर थे। यह आशा है कि उपर्युक्त योजना के शुरू किए जाने से हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहनों, एलसीवी और बसों सहित सभी वाहन क्षेत्रों में बाजार में तेजी आएगी।

(घ) और (ङ): उपर्युक्त में, सरकार की योजना क्रेताओं को ये हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय मौद्रिक सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करना है। भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में अनुमोदित फेम स्कीम के अंतर्गत विभिन्न हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मौद्रिक सहायता (प्रोत्साहन प्रति वाहन-प्रौद्योगिकी वार) सहित इस योजना के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया है। प्रोत्साहन संवितरण के लिए प्रोत्साहन योजना को एक दक्ष एवं प्रभावी इलेक्ट्रिक पद्धति/पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा। इस पद्धति के तहत, विनिर्माता क्रेता को हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहन बेचते समय खरीद मूल्य में कमी करेगा (खरीद मूल्य में पात्र पूर्व निर्धारित प्रोत्साहन राशि के स्तर तक कमी की जाएगी) और इन्हें इसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

******